SAARTHI · सारथी

करियर मार्गदर्शन पोर्टल · Career Guidance Portal

"सही मार्गदर्शन, उज्ज्वल भविष्य।"

करियर शीट · CAREER SHEET

Junior Judicial Assistant — Rajasthan High Court

कनिष्ठ न्यायिक सहायक राजस्थान उच्च न्यायालय के कर्मचारी-वर्ग का प्रवेश-पद है। न्यायालय केवल न्यायाधीशों से नहीं चलता — प्रत्येक वाद की पत्रावली, आदेशों की प्रतिलिपियाँ, वाद-सूची, अभिलेख एवं पक्षकारों से पत्राचार एक स्थायी...

इस करियर की पूरी जानकारी — स्कैन करें

वेतन, परीक्षा, कॉलेज, प्रवेश के रास्ते और आगे के कदम — सब पोर्टल पर।

career.gsssjethantri.in/#/career/raj-junior-judicial-assistant

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेठन्तरी

Govt. Sr. Sec. School, Jethantri · ब्लॉक समदड़ी · बालोतरा (Block Samdari · Balotra)

www.gsssjethantri.in · career.gsssjethantri.in

सुशील कुमार शर्मा
प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि. जेठन्तरी · मास्टर ट्रेनर
Principal, GSSS Jethantri · Master Trainer

श्री चेनाराम चौधरी
प्रधानाचार्य, डाइट बाड़मेर
Principal, DIET Barmer

श्रीमती संघमित्रा
वरिष्ठ व्याख्याता, डाइट बाड़मेर (सहयोग)
Sr. Lecturer, DIET Barmer (Support)

भरत चौधरी
अभिकल्पना व विकास · व्याख्याता (इतिहास)
Designed & developed · Lecturer (History)

विशेष धन्यवाद · SPECIAL THANKS

सुरेन्द्र सिंह राठौड़
व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. कानाना

सुरेश कुमार सैन
व्याख्याता (भूगोल) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा

वनिता कुमारी
व्याख्याता (इतिहास) · रा.उ.मा.वि. रामसीन मूंगड़ा

कमलेश चौधरी
व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) · रा.उ.मा.वि. टापरा

करियर मार्गदर्शन कार्यशाला, डाइट बाड़मेर (14–17 जुलाई 2026) में विकसित व लोकार्पित
Developed & unveiled at the Career Guidance Workshop, DIET Barmer (14–17 July 2026)

यह एक स्वतंत्र परियोजना है, जो सरकार की आधिकारिक करियर-मार्गदर्शन सामग्री पर आधारित है। · An independent project based on the Government's official career-guidance content.

1 यह करियर क्या है

कनिष्ठ न्यायिक सहायक राजस्थान उच्च न्यायालय के कर्मचारी-वर्ग का प्रवेश-पद है। न्यायालय केवल न्यायाधीशों से नहीं चलता — प्रत्येक वाद की पत्रावली, आदेशों की प्रतिलिपियाँ, वाद-सूची, अभिलेख एवं पक्षकारों से पत्राचार एक स्थायी कर्मचारी-तंत्र सँभालता है, और यह पद उसी तंत्र का आधार है। यह उन थोड़े रास्तों में से है जहाँ कोई भी स्नातक — कला, वाणिज्य अथवा विज्ञान से — सीधे न्यायपालिका के भीतर काम करने पहुँच सकता है, बिना विधि की डिग्री के। भर्ती न्यायालय स्वयं करता है, अपनी प्रतियोगी परीक्षा से, और अपने ही सेवा नियमों के अंतर्गत — राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के नियमों से नहीं। यह भेद व्यावहारिक है: विज्ञप्ति, पाठ्यक्रम एवं परिणाम सब उच्च न्यायालय की अपनी वेबसाइट पर आते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर नहीं।

2 एक नज़र में

न्यूनतम योग्यता	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा, तथा कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान — नियम किसी विशिष्ट प्रमाण-पत्र का नाम नहीं लेता
भर्ती संस्था	राजस्थान उच्च न्यायालय — भर्ती न्यायालय स्वयं करता है, अपने कर्मचारी सेवा नियम, 2002 के अंतर्गत
आयु-सीमा	18 से 40 वर्ष, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आने वाली 1 जनवरी को (नियम 8) — आरक्षित वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु-सीमा में छूट मिलती है (विवरण नीचे)
आरंभिक वेतन	सेवा नियमों में पे मैट्रिक्स का स्तर नहीं दिया — विज्ञप्ति देखें
माँग	प्रतियोगी परीक्षा से सीधी भर्ती, किंतु 15% पद पदोन्नति हेतु आरक्षित तथा 15% तक मुख्य न्यायाधिपति के विवेक से समावेशन द्वारा भरे जा सकते हैं

3 क्या-क्या चाहिए

रुचियाँ

- न्यायालय, विधि-प्रक्रिया एवं अभिलेख के काम में रुचि
- व्यवस्थित एवं सावधान लिखित कार्य

- न्यायपालिका के भीतर काम करना, बिना विधि की डिग्री के

क्षमताएँ

- सटीकता — न्यायालय के अभिलेख में एक चूक किसी पक्षकार के मामले को प्रभावित करती है
- कंप्यूटर पर गति एवं शुद्धता — चयन में इसकी अलग परीक्षा होती है
- हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनों पर पकड़, क्योंकि परीक्षा एवं काम दोनों में दोनों चलती हैं

ज़रूरी कौशल

- कंप्यूटर पर आँकड़ा-प्रविष्टि, अंग्रेज़ी अथवा हिंदी-अंग्रेज़ी दोनों में
- वाद-सूची, आदेश-प्रतिलिपि एवं पत्राचार का काम
- सामान्य ज्ञान — लिखित परीक्षा का एक तिहाई भाग
- न्यायालय की पत्रावली एवं अभिलेख का रखरखाव
- हिंदी एवं अंग्रेज़ी में सामान्य लेखन
- गोपनीयता एवं निष्पक्षता, क्योंकि सामग्री विचाराधीन मामलों की होती है

4 कैसे पहुँचें

1. कक्षा 12 किसी भी संकाय से उत्तीर्ण करें, फिर किसी भी विषय में स्नातक करें। नियम केवल इतना कहता है कि अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का स्नातक हो अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो — विषय की कोई शर्त नहीं, और विधि की डिग्री आवश्यक नहीं।
2. कंप्यूटर की शर्त पर ध्यान दें, क्योंकि यह वही नहीं है जो राज्य सरकार के लिपिकीय पदों पर लगती है। यहाँ नियम केवल "कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान" माँगता है और किसी विशिष्ट प्रमाण-पत्र का नाम नहीं लेता। तुलना करें: राजस्थान सचिवालय के लिपिक ग्रेड-II पद पर नियम आर.एस.-सी.आई.टी. जैसी नामित योग्यताओं की सूची देता है और उनमें से एक अनिवार्य है। दोनों पद लिपिकीय हैं और साथ-साथ दिखते हैं, पर उनकी शर्त अलग है — इसलिए एक के आधार पर दूसरे का अनुमान न लगाएँ।
3. इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि इस पद के लिए कोई प्रमाण-पत्र खरीदना आवश्यक नहीं है। जो चीज़ वास्तव में चाहिए वह कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता है, और उसकी परीक्षा चयन में अलग से होती है — इसलिए पैसा पाठ्यक्रम पर नहीं, अभ्यास पर लगाइए।
4. कंप्यूटर पर टंकण की गति बनाएँ, और इसे तैयारी के आरंभ से रखें। चयन के दूसरे चरण में गति परीक्षा होती है जिसमें न्यूनतम 8,000 डिप्रेशन प्रति घंटा आवश्यक है, और आँकड़े अंग्रेज़ी में अथवा दोनों भाषाओं — अंग्रेज़ी एवं हिंदी — में भरने होते हैं। यह परीक्षा 100 अंकों की होती है, जिसमें गति एवं दक्षता के 50-50 अंक हैं, और अवधि दस मिनट है।
5. आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जिसकी गणना आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आने वाली 1 जनवरी को होती है। ध्यान दें कि यह सामान्य गणना है — सचिवालय की मंत्रालयिक सेवा में यह 1 अप्रैल को होती है, इसलिए दोनों को एक न मानें।
6. विज्ञप्ति उच्च न्यायालय की अपनी वेबसाइट पर आती है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर नहीं। यह भेद जान लेना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी ग़लत जगह देखता रह जाता है।

प्रमुख परीक्षाएँ

- चयन दो खंडों में होता है और दोनों अनिवार्य हैं। खंड-क लिखित परीक्षा है: एक प्रश्न-पत्र, कुल 300 अंक, तीन भागों में बराबर बँटा — भाग क हिंदी 100 अंक, भाग ख अंग्रेज़ी 100 अंक, भाग ग सामान्य ज्ञान 100 अंक। प्रत्येक भाग में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न दो अंकों का। अवधि दो घंटे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि भाषा को दो-तिहाई भार मिला है — हिंदी एवं अंग्रेज़ी मिलकर 200 अंक, सामान्य ज्ञान केवल 100। यह अधिकांश लिपिकीय भर्तियों से भिन्न है, जहाँ सामान्य ज्ञान एवं गणित का भार बड़ा होता है।
- अब वह बात जो इस पद पर सबसे अधिक भ्रम पैदा करती है, और उसका उत्तर सुखद है: कंप्यूटर की शर्त केवल "प्रारंभिक ज्ञान" की है। नियम में किसी प्रमाण-पत्र का नाम नहीं है — न आर.एस.-सी.आई.टी., न डोएक, न कोपा। पहले नियम में इन सबकी सूची थी और उसे 2014 की अधिसूचना से हटाकर यह सामान्य वाक्य रखा गया। इसकी पुष्टि इसी नियमावली के दूसरे पद से भी होती है: कनिष्ठ निजी सहायक की योग्यता में भी ठीक यही वाक्य है, अपने अलग फुटनोट के साथ — अर्थात् यह सरलीकरण न्यायालय के नियमों में एक साथ किया गया था, केवल इसी पद पर नहीं।
- खंड-ख कंप्यूटर पर टंकण की गति परीक्षा है। न्यूनतम गति 8,000 डिप्रेशन प्रति घंटा है और आँकड़े अंग्रेज़ी में अथवा अंग्रेज़ी एवं हिंदी दोनों में भरने होते हैं। यह 100 अंकों की है — गति के 50 एवं दक्षता के 50 — और दस मिनट की। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक (विशेष योग्यजन तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 40%) प्राप्त करने वाले ही इस चरण के लिए पात्र होते हैं, और वह भी रिक्तियों की संख्या के 15 गुना तक की सीमा में। अर्थात् लिखित परीक्षा छँटनी करती है और टंकण परीक्षा अंतिम निर्णय में गिनी जाती है।
- रिक्तियों के बारे में एक बात ईमानदारी से जान लेनी चाहिए, क्योंकि विज्ञप्ति में दी गई संख्या पूरी तरह खुली प्रतियोगिता के लिए नहीं होती। नियम के अनुसार कुल रिक्तियों का 15% न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से पदोन्नति के लिए आरक्षित है, बशर्ते उन्होंने पाँच वर्ष की सेवा की हो एवं वरिष्ठ माध्यमिक (10+2) उत्तीर्ण हों। इसके अतिरिक्त 15% तक पद मुख्य न्यायाधिपति के विवेक से उच्च न्यायालय के तकनीकी कर्मचारियों में से समावेशन (अब्ज़ॉर्प्शन) द्वारा भरे जा सकते हैं। अर्थात् बाहर से आने वाले अभ्यर्थी के लिए वास्तविक हिस्सा 70% के आसपास रह सकता है।

- नाम-परिवर्तनों का एक पूरा समूह 2004 में हुआ था और पुरानी सामग्री पढ़ते समय वह भ्रम पैदा करता है। निम्न श्रेणी लिपिक का नाम बदलकर कनिष्ठ न्यायिक सहायक हुआ — अर्थात् यही पद; उच्च श्रेणी लिपिक न्यायिक सहायक बना; कार्यालय सहायक वरिष्ठ न्यायिक सहायक; आशुलिपिक कनिष्ठ निजी सहायक; तथा अधीक्षक प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)। यदि आपको कहीं पुराने नाम मिलें, तो वे इन्हीं पदों की बात कर रहे हैं।
- ऊपरी आयु-सीमा में छूट — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष; तथा इन्हीं वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष। इसका सीधा अर्थ यह है कि किसी पद के आगे लिखी बिना छूट वाली आयु किसी आरक्षित वर्ग की महिला के लिए दस वर्ष कम बताती है — यदि आप उस श्रेणी में हैं तो अपनी पात्रता छूट जोड़कर ही तय करें। राजस्थान में सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% पद श्रेणीवार आरक्षित रहते हैं। विधवा एवं परित्यक्ता (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए कोई ऊपरी आयु-सीमा नहीं — नियमों में यही शब्द हैं। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के नियम 13(9) में, तथा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियमों के इसी परंतुक में यह प्रावधान दर्ज है, और आर.पी.एस.सी. की विज्ञप्तियाँ भी इसे दोहराती हैं। विधवा को सक्षम अधिकारी से पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र और परित्यक्ता को तलाक का प्रमाण देना होता है। छूट एवं आरक्षण की सटीक शर्तें उसी भर्ती की विज्ञप्ति में दी जाती हैं।

5 कहाँ से पढ़ें

सरकारी संस्थान

- University of Rajasthan and the state universities — a graduation in any subject qualifies — जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर एवं कोटा (https://uniraj.ac.in/)
- Government colleges across Rajasthan — B.A., B.Com. and B.Sc. at very low fees — लगभग हर ज़िले में (https://hte.rajasthan.gov.in/)
- Vardhman Mahaveer Open University, Kota — for completing a graduation alongside work — कोटा, राजस्थान (https://www.vmou.ac.in/)
- Government ITIs and polytechnics — computer and data entry practice at low cost, though no certificate is required for this post — राजस्थान के अनेक ज़िलों में (https://dte.rajasthan.gov.in/)

ऑनलाइन

- राजस्थान उच्च न्यायालय — भर्ती की सूचनाएँ यहीं आती हैं, बोर्ड की साइट पर नहीं — जोधपुर एवं जयपुर पीठ (https://hcraj.nic.in/hcraj/recruitment.php)
- राजस्थान उच्च न्यायालय — नियमावली, जिसमें कर्मचारी सेवा नियम 2002 भी है — योग्यता एवं परीक्षा-योजना मूल दस्तावेज़ में पढ़ें (https://hcraj.nic.in/hcraj/rules.php)
- राजस्थान उच्च न्यायालय — मुख्य वेबसाइट — न्यायालय का आधिकारिक पोर्टल (https://hcraj.nic.in/)

- आर.एस.एस.बी. — पिछले प्रश्न-पत्र, उत्तर कुंजी व पाठ्यक्रम (निःशुल्क) — राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक साइट — तैयारी के लिए सबसे भरोसेमंद निःशुल्क सामग्री (https://rsmssb.rajasthan.gov.in/show_archived?menuName=Xj4lCb9vGxpQnfLs%2FxlZ2g%3D%3D)
- विभागीय सेवा नियम (कार्मिक विभाग) — पद की योग्यता व आयु मूल दस्तावेज़ में पढ़ें — कार्मिक विभाग हर संवर्ग के सेवा नियम प्रकाशित करता है। किसी भी कोचिंग सामग्री से पहले यही पढ़ें — योग्यता, आयु और भर्ती की विधि यहीं तय होती है। (https://dop.rajasthan.gov.in/)
- स्वयं (SWAYAM) — भारत सरकार के निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स — निःशुल्क (https://swayam.gov.in/)
- राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (NDLI) — निःशुल्क पुस्तकें व अध्ययन सामग्री (https://ndl.iitkgp.ac.in/)
- एन.सी.ई.आर.टी. — निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें — सामान्य ज्ञान, गणित व विज्ञान की नींव (https://ncert.nic.in/)

फ़ीस

यह इस पोर्टल की सबसे सस्ती स्नातक-स्तरीय राहों में से एक है, और उसका कारण एक विशिष्ट बात है। योग्यता किसी भी विषय में स्नातक होना है, जो राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में बहुत कम शुल्क पर हो जाता है और लगभग हर ज़िले में उपलब्ध है; यदि पढ़ाई काम के साथ करनी हो तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से भी की जा सकती है। और कंप्यूटर की शर्त पर यहाँ कोई पैसा नहीं लगता: नियम केवल "प्रारंभिक ज्ञान" माँगता है और किसी प्रमाण-पत्र का नाम नहीं लेता, इसलिए आर.एस.-सी.आई.टी. अथवा कोई अन्य पाठ्यक्रम खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यह इस पोर्टल के अनेक अन्य लिपिकीय पदों से भिन्न है, जहाँ ऐसा प्रमाण-पत्र अनिवार्य है — और यही अंतर इस पद को उन विद्यार्थियों के लिए सुलभ बनाता है जिनके पास पाठ्यक्रम का शुल्क नहीं है। जो निवेश वास्तव में आवश्यक है वह समय का है: कंप्यूटर पर टंकण का नियमित अभ्यास, क्योंकि चयन के दूसरे चरण में 8,000 डिप्रेशन प्रति घंटा की गति चाहिए और वह अभ्यास से ही बनती है, किसी पाठ्यक्रम से नहीं। यह अभ्यास किसी भी साधारण कंप्यूटर पर निःशुल्क किया जा सकता है। साथ ही हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनों पर काम करें, क्योंकि लिखित परीक्षा के 300 में से 200 अंक इन्हीं दो भाषाओं के हैं। एक चेतावनी: भर्ती दिलाने का दावा करने वाले किसी बिचौलिये को पैसा न दें — चयन केवल न्यायालय की अपनी परीक्षा से होता है।

छात्रवृत्तियाँ

- Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana (free coaching, apply via SSO) (https://sso.rajasthan.gov.in/signin)
- Rajasthan Social Justice and Empowerment Dept scholarships (https://sje.rajasthan.gov.in/)
- National Scholarship Portal (NSP) (https://scholarships.gov.in/)
- Buddy4Study scholarship search (https://www.buddy4study.com)

6 काम कैसा होता है

कहाँ काम

राजस्थान उच्च न्यायालय — जोधपुर की प्रधान पीठ तथा जयपुर पीठ। काम पूरी तरह न्यायालय परिसर के भीतर होता है।

कार्य-संस्कृति

न्यायालय का कर्मचारी-कार्य अपनी लय में चलता है और उसे समझ लेना चाहिए। दिन न्यायालय के समय से बँधा रहता है: वाद-सूची, पत्रावलियाँ, आदेशों की प्रतिलिपियाँ, तथा अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों से व्यवहार। काम का दबाव मौसमी होता है — सुनवाई के व्यस्त दिनों एवं अवकाश से पहले की अवधि में समय-सीमा कड़ी हो जाती है। इस पद की एक विशेषता यह है कि यहाँ सटीकता का महत्त्व सामान्य लिपिकीय काम से अधिक है: जो तिथि, नाम अथवा आदेश आप अभिलेख में दर्ज करते हैं वह किसी व्यक्ति के मुक़दमे का हिस्सा बनता है, और उसमें हुई चूक उस व्यक्ति को भुगतनी पड़ती है। इसी कारण गोपनीयता एवं निष्पक्षता यहाँ पेशेवर अनुशासन हैं, केवल औपचारिकता नहीं — कर्मचारी विचाराधीन मामलों की सामग्री देखता है। वातावरण औपचारिक एवं पदानुक्रम स्पष्ट रहता है। इसके बदले में जो मिलता है वह असामान्य है: विधि की डिग्री के बिना न्यायपालिका के भीतर स्थायी सेवा, न्यायालय की प्रक्रिया की निकट से समझ, तथा एक ऐसा संस्थान जिसकी अपनी सेवा नियमावली है और जो अपनी भर्ती स्वयं करता है।

कौन नौकरी देता है

- राजस्थान उच्च न्यायालय — जोधपुर की प्रधान पीठ
- राजस्थान उच्च न्यायालय — जयपुर पीठ
- अधीनस्थ न्यायालयों के मंत्रालयिक संवर्ग, जो अलग नियमावली से चलते हैं — जिला न्यायालय मंत्रालयिक स्थापना नियम, 1986
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायालय से जुड़े निकाय

माँग (2026)

उच्च न्यायालय का कर्मचारी-वर्ग स्थायी है और उसका काम कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए इस संवर्ग की आवश्यकता बनी रहती है। साथ में तीन बातें ईमानदारी से जान लेनी चाहिए। पहली, संवर्ग का आकार सीमित है और भर्ती हर वर्ष नहीं आती — यह राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की बड़ी नियमित भर्तियों जैसी नहीं है, इसलिए इस पर अकेले निर्भर नहीं रहा जा सकता। दूसरी, विज्ञप्ति में दी गई रिक्तियों का पूरा हिस्सा खुली प्रतियोगिता के लिए नहीं होता: 15% पदोन्नति हेतु आरक्षित है और 15% तक समावेशन से भरे जा सकते हैं। तीसरी, प्रतिस्पर्धा तीव्र है, क्योंकि योग्यता केवल स्नातक होना है और कोई प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं — यही सुलभता आवेदकों की संख्या बढ़ा देती है। इसके विरुद्ध जो सुविधा है वह वास्तविक है: वही स्नातक योग्यता एवं वही तैयारी — हिंदी, अंग्रेज़ी, सामान्य ज्ञान एवं कंप्यूटर टंकण — राजस्थान सचिवालय के लिपिक, कनिष्ठ सहायक, तथा अधीनस्थ न्यायालयों के मंत्रालयिक पदों में भी काम आती है। पदों की संख्या न्यायालय की आवश्यकता बताती है, आपके चयन की संभावना नहीं। एक बात स्पष्ट रहे — ऊपर दी गई "माँग" पदों की संख्या बताती है, आपके चयन की संभावना नहीं। चयन खुली प्रतियोगिता से होता है और आवेदन करने वालों की संख्या पदों से कई गुना अधिक रहती है, इसलिए अधिकांश अभ्यर्थी किसी एक भर्ती में चयनित नहीं हो पाते। यह इस करियर के विरुद्ध तर्क नहीं है — बस इसे अपनी एकमात्र योजना न बनाएँ। तैयारी के साथ-साथ पढ़ाई जारी रखें या कोई कौशल सीखें, ताकि परिणाम चाहे जो हो, वर्ष व्यर्थ न जाए।

7 आगे बढ़ने का रास्ता

1. कनिष्ठ न्यायिक सहायक — प्रवेश-पद (2004 से पहले इसे निम्न श्रेणी लिपिक कहा जाता था)
2. न्यायिक सहायक — पदोन्नति द्वारा (पूर्व नाम उच्च श्रेणी लिपिक)
3. वरिष्ठ न्यायिक सहायक — आगे की पदोन्नति पर (पूर्व नाम कार्यालय सहायक)

4 प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) एवं उससे ऊपर — न्यायालय के कर्मचारी-वर्ग का वरिष्ठ स्तर (पूर्व नाम अधीक्षक)

कमाई

शुरुआत	विज्ञप्ति में घोषित पे मैट्रिक्स स्तर के अनुसार
मध्य स्तर	₹30,000 – ₹45,000 (भत्तों सहित, न्यायिक सहायक के स्तर पर)
वरिष्ठ स्तर	₹55,000 से अधिक (भत्तों सहित, वरिष्ठ न्यायिक सहायक एवं उससे ऊपर)

2002 के कर्मचारी सेवा नियमों में इस पद का पे मैट्रिक्स स्तर नहीं दिया गया — नियमावली वेतनमान को मुख्य न्यायाधिपति के आदेश एवं अन्य नियमों पर छोड़ती है। इसलिए आरंभिक वेतन इस पृष्ठ पर आँकड़े के रूप में नहीं लिखा गया; वह उसी चक्र की विज्ञप्ति में मिलेगा, और वही एकमात्र भरोसेमंद स्रोत है। ऊपर दिए मध्य एवं वरिष्ठ स्तर के आँकड़े अनुमानित हैं और किसी आधिकारिक वेतन-पत्रक से पुष्ट नहीं; उन्हें दिशा समझें, वचन नहीं। एक बात ध्यान में रखने योग्य है: यह न्यायालय का अपना संवर्ग है और उसकी सेवा-शर्तें राज्य सरकार के लिपिकीय संवर्गों से भिन्न नियमावली के अंतर्गत आती हैं, इसलिए दोनों के वेतन की सीधी तुलना विज्ञप्ति देखे बिना नहीं करनी चाहिए। शुरुआती वेतन का आँकड़ा मूल वेतन है, ताकि इसे दूसरे करियर के साथ सीधे तुलना किया जा सके। इस पर महँगाई भत्ता (1 जनवरी 2026 से मूल वेतन का 60%) एवं मकान किराया भत्ता अलग से जुड़ते हैं, इसलिए हाथ में आने वाली राशि इससे काफ़ी अधिक होती है। मध्य-स्तर व वरिष्ठ स्तर के आँकड़े भत्तों सहित अनुमानित मासिक आय हैं, मूल वेतन नहीं। ध्यान दें — राजस्थान में सीधी भर्ती से लगे कर्मचारी पहले 2 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी रहते हैं और इस अवधि में वेतनमान नहीं, बल्कि एक नियत पारिश्रमिक मिलता है; इन दो वर्षों में महँगाई भत्ता व मकान किराया भत्ता देय नहीं होते (राजस्थान सेवा नियम, नियम 7(30क))। पूरा वेतनमान परिवीक्षा पूरी होने के बाद लागू होता है। इस पद का पे मैट्रिक्स स्तर इस पृष्ठ पर आधिकारिक दस्तावेज़ से पुष्ट नहीं किया जा सका — न सेवा नियमों में, न सी.ई.टी. नियम 2022 की अनुसूची में। इसलिए यहाँ कोई स्तर नहीं लिखा गया है। सही आँकड़ा उस भर्ती की आधिकारिक विज्ञप्ति में दिया जाता है; आवेदन से पहले उसे अवश्य देखें। ऊपर दिए गए आँकड़े राजस्थान के सातवें वेतन मैट्रिक्स पर आधारित हैं, जो 17 अगस्त 2026 तक लागू है। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की शर्तें 28 अक्टूबर 2025 को स्वीकृत हुई थीं और आयोग को गठन से 18 माह के भीतर सिफ़ारिशें देनी हैं। राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशें आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ, और कुछ देर से, लागू करती हैं — इसलिए राजस्थान का वेतनमान भी आगे संशोधित होगा, यद्यपि कब और कितना, यह अभी तय नहीं है।

8 अच्छी बातें · चुनौतियाँ

अच्छी बातें

- कंप्यूटर की शर्त पर कोई प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं — केवल प्रारंभिक ज्ञान, जो इस पोर्टल के अनेक लिपिकीय पदों से भिन्न है
- विधि की डिग्री के बिना न्यायपालिका के भीतर स्थायी सेवा, किसी भी विषय के स्नातक के लिए
- तैनाती जोधपुर अथवा जयपुर में स्थिर रहती है
- लिखित परीक्षा में भाषा का भार दो-तिहाई — हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी के लिए यह अनुकूल है

चुनौतियाँ

- रिक्तियों का 15% पदोन्नति हेतु आरक्षित तथा 15% तक समावेशन से — खुली प्रतियोगिता का हिस्सा कम
- भर्ती हर वर्ष नहीं आती और संवर्ग का आकार सीमित है
- टंकण की गति परीक्षा अनिवार्य — 8,000 डिप्रेशन प्रति घंटा, जिसके लिए महीनों का अभ्यास चाहिए
- विज्ञप्ति न्यायालय की अपनी साइट पर आती है, इसलिए बोर्ड की साइट देखते रहने वाले अभ्यर्थी चूक जाते हैं

9 अगर यह रास्ता न बने तो

एक परीक्षा या एक प्रयास से रास्ता बंद नहीं होता। इन्हीं विषयों से ये रास्ते भी खुलते हैं — इनमें प्रवेश आमतौर पर आसान होता है और आगे चलकर इसी क्षेत्र में लौटा जा सकता है।

- आशुलिपिक व निजी सहायक ग्रेड-II (राजस्थान सरकार)
- लिपिक ग्रेड-II — राजस्थान सचिवालय
- पटवारी (राजस्व विभाग, राजस्थान)

10 स्रोत व आगे पढ़ें

1. राजस्थान उच्च न्यायालय — कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (22.07.2026 तक संशोधित) — https://hcraj.nic.in/hcraj/hcraj_admin/uploadfile/rule/uploaded178479922536.pdf

2. राजस्थान उच्च न्यायालय — भर्ती — https://hcraj.nic.in/hcraj/recruitment.php

3. राजस्थान उच्च न्यायालय — नियमावली — https://hcraj.nic.in/hcraj/rules.php

4. राजस्थान उच्च न्यायालय — मुख्य वेबसाइट — https://hcraj.nic.in/

5. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आधिकारिक) — https://rssb.rajasthan.gov.in/

6. कार्मिक विभाग, राजस्थान — सेवा नियम — https://dop.rajasthan.gov.in/

7. आठवाँ केंद्रीय वेतन आयोग — मंत्रिमंडल की स्वीकृति (पी.आई.बी., 28 अक्टूबर 2025) — https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183289

और 770+ करियर — पूरा पोर्टल

रुचि व योग्यता परीक्षण, सरकारी नौकरियाँ, कौशल पाठ्यक्रम, बायोडाटा बनाने की सुविधा — सब मुफ़्त, बिना लॉगिन, इंटरनेट के बिना भी।

career.gsssjethantri.in